

अगले तीन वर्ष में प्रदेश की सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जाए: डॉ. यादव

सड़कों के संधारण और उन्नयन में भारत सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम



भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की शत-प्रतिशत बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए समय-सिमा निर्धारित कार्रवाई करें।

सभी जिलों में सड़कों की आवश्यकता का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे सुनिश्चित कर कार्य-योजना बनाई जाए। सड़कों की आवश्यकता के संबंध में विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों का अभिमत अवश्य लिया जाए। राज्य सरकार अगले तीन वर्ष में सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के

दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि, बाढ़ तथा अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत और उनके उन्नयन की आवश्यकता के प्रति सतर्क रहते हुए तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाए। सड़कों के रख-रखाव और नियमित निरीक्षण में मोबाइल एप, जियो टैगिंग तथा एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर इसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। सड़कों पर वर्तमान यातायात का सर्वे कर उन्नयन और लेन विस्तारिकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पाण्डोला से बीजाटोला तक देश की पहली सड़क का निर्माण बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में किया गया है। सड़कों के संधारण और उन्नयन के लिए भारत सरकार से प्रोत्साहन

राशि प्राप्त करने में प्रदेश, देश में प्रथम रहा है। प्रदेश में मार्गों के संधारण के लिए वर्ष 2015-16 से लागू ई-मार्ग पोर्टल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसे सम्पूर्ण देश में नेशनल ई-मार्ग के रूप में लागू किया गया है।

बताया गया कि प्रदेश की 89 हजार बसाहटों में से 50 हजार 658 बसाहटों तक रोड़ कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर ली गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के अंतर्गत बनने वाली 11 हजार 544 बसाहटों के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 26 हजार 798 बसाहटों की कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सामान्य संधारण कार्यों का प्रावकलन तैयार करने और तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति आदि की ऑनलाइन व्यवस्था स्म्वेग पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है।

मंत्री चौहान ने बनासकांठा पहुंच कर घायल श्रमिकों का जाना हाल, बंधाया ढांडस

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने अधिकारी-कर्मचारियों के साथ देर रात गुजरात के बनासकांठा पहुंचकर प्रदेश के घायल श्रमिकों एवं उनके परिजन से मुलाकात कर हाल-चाल जाना।

श्री चौहान ने घायल श्रमिकों के परिजन से बात कर उन्हें ढांडस बंधाया। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा घायल मजदूरों के उचित इलाज और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुजरात, बनासकांठा में घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन से जानकारी प्राप्त की। बनासकांठा जिले के डीसा अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों के इलाज के लिये उचित प्रबंध के निर्देश दिए। साथ ही घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि



स्थानीय प्रशासन दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी करेगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हादसे में मृतक एवं घायल श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश सरकार ने पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायल मृतकों के परिजनों को रुपये 2-2 लाख तथा घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपये और गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये एवं

घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने शोक व्यक्त किया

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना पर गहन शोक व्यक्त किया है। श्री देवड़ा ने कहा कि दुर्घटना में मध्यप्रदेश के कई श्रमिकों की मृत्यु तथा कुछ श्रमिकों के गंभीर रूप से घायल

होने की घटना अत्यंत दुःख एवं हृदयविकारक है। श्री देवड़ा ने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं को अपने शीघ्रतः स्वस्थ दें, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें एवं शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विकट घड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गुजरात सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है।

मृतकों की पार्थिव देह जल्द ही उनके घर पहुंचायी जाएगी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गुजरात के बनासकांठा स्थित पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना अत्यंत दुःख और कष्टदायी है। राज्य सरकार पूरी सक्रियता एवं तत्परता के साथ मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ितों की सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे हैं। मृतकों की पार्थिव देह उनके गृहग्राम एवं परिजन तक पहुंचाने की सभी जरूरी व्यवस्थाएं तेजी से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मीडिया को जारी संदेश में सभी मृतकों के परिजन के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से हादसे का शिकार हुए सभी मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जायेगी। डॉ. यादव ने काम के सिलसिले में राज्य की सीमा से बाहर जाने वाले सभी श्रमिकों से अपने काम के दौरान पूरी सतर्कता बरतने एवं खुद की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील भी की है।

जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की साजिश रचने वाले...

ज्यारहवां फरार आरोपी फिरोज उर्फ सब्जी गिरफ्तार

भोपाल(काप्र)।

थाना निंबाहेड़ा राजस्थान पुलिस द्वारा दिनांक 30.03.22 को चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी लेते उसमें तीन व्यक्तियों जुबेर पिता फकीर मोहम्मद पठान, सैफुल्ला उर्फ सैफ खान पिता रमजानी अली एवं अल्लतमश पिता बशीर खां तीनों निवासी रतलाम को विस्फोटक एवं बम बनाने में प्रयुक्त होने वाला सामान जिसमें टायमर, सेल, वायर सहित अन्य सामग्री के साथ पकड़ा।

पूछताछ के दौरान तीनों व्यक्तियों खूंखार अलसुफा नामक संगठन से जुड़े थे। जो अपने संगठन सुफा के अन्य 8 सदस्यों आमीन फावड़ा, आमीन हाजी, मजहर

उर्फ छोद्दा, इमरान पठान, युनुस साकी, इमरान मटका, आकिब महाराष्ट्र एवं फिरोज उर्फ सब्जी के साथ उक्त विस्फोटक पदार्थ के द्वारा जयपुर में सीरियल ब्लास्ट कर आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। थाना निंबाहेड़ा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 150/22 धारा 4,5,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 13, 15, 16, 18 एवं 20 यूएपीए के तहत पंजीबद्ध किया गया। उक्त मामला अंतरराज्यीय होने पर एनआईए द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2022/एआईए/डीएलआई दर्ज किया गया। प्रकरण में एनआईए एवं राजस्थान पुलिस द्वारा 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 11वां आरोपी फिरोज उर्फ सब्जी जो अलसुफा संगठन के प्रमुख 05 संस्थापक सदस्यों में से एक था, जिसके पास संगठन के खजाने का पद

था जो फरार चल रहा था। जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। जिसकी गिरफ्तारी पर एन आई ए द्वारा रुपए 05 लाख रुपए के इनाम की उद्घोषणा की गई थी। पुलिस अधीक्षक रतलाम के निर्देशन पर रतलाम में अलसुफा संगठन एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में 2.4.2025 को मुखबिर से प्राप्त हुई कि पांच लाख रुपए का इनामी आरोपी फिरोज उर्फ सब्जी पिता फकीर मोहम्मद रतलाम शहर में गंभीर घटना कारीत करने के उद्देश्य से आया हुआ है।

मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर 4 अलग-अलग टीम बनाकर शहर में खोजबीन शुरू की गई। फरार आरोपी के छिपने के संभावित ठिकानों के आसपास पुलिस टीम द्वारा गोपनीय तरीके से सर्चिंग करते हुए मुखबिर सक्रिय किए गए। मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि वांटेड आरोपी फिरोज उसकी बहन रेहाना निवासी आनंद कॉलोनी के घर छिपा हुआ है। दिनांक 2.4.2025 को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रतलाम पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त उद्घोषित आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान संभावित खतरे के संबंध में विस्तृत रूप से ब्रीफिंग कर टीम के साथ मुखबिर के बताए स्थान आनंद कालोनी रवाना हुए। आनंद कालोनी स्थित रेहाना के निवास के समीप पहुंचकर ब्रीफिंग अनुसार कट ऑफ टीम के सदस्यों द्वारा घेराबंदी की गई। योजना अनुसार स्ट्राइकिंग टीम के सदस्यों द्वारा निवास स्थल पर पहुंच कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी फिरोज द्वारा झुमा झटकी कर भागने का प्रयास किया जिसे काफी मशकत के बाद नियंत्रण में लेकर गिरफ्तार किया गया।

केरिपु बल की 41वीं बटालियन ने मनाया स्थापना दिवस

भोपाल(काप्र)।

41वीं बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपुब) ने अपना 58वां स्थापना दिवस बड़े ही भव्य तरीके से मनाया।

गौरतलब है कि इसी दिन सन् 1968 को राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेब्युलरी की 11वीं बटालियन को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 41वीं वाहिनी में परिवर्तित कर तत्कालीन नेफा अर्थात् अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थापना हेतु भेजा गया था। तब से बटालियन देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यकतानुसार अपनी सेवाएं देते हुए, 2009 से अपने वर्तमान कैम्पस बंगरसिया में अवस्थित है। बटालियन कमाण्डेंट मनीष कुमार यादव ने बताया कि पिछले वर्ष कम्पनीयों न सिर्फ संसद और विधानसभा चुनावों

के सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु लड़ाख से केरल, पश्चिमबंगाल से गुजरात तक तैनात रही अपितु श्री अमरनाथजी यात्रा, कश्मीर एवं दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुम्भ, प्रयागराज में भी अपनी सेवाएं दी हैं। कार्यक्रम का समापन एक रंगारंग सांस्कृतिक संध्या एवं बड़ा खाना से हुआ। सुमनकांत तिग्गा (पीएमजी), महानिरीक्षक केरिपु बल मप्र सैक्टर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

समारोह के दौरान प्रतिभागियों ने भारत के विभिन्न रंग एवं संस्कृति की झलक को प्रदर्शित किया एवं नाटिका के जरिये संदेश दिया। श्री तिग्गा ने कहा कि श्री यादव, कमाण्डेंट के कुशल नेतृत्व में बटालियन समस्त चुनौतियों से नक्सलवाद, आतंकवाद, चुनाव व कानूनव्यवस्था के हालातों का मुकाबला बखूबी कर रही है। इस अवसर पर नीतू डी भट्टाचार्य, उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ अधिकारिगण उपस्थित रहे।



प्रदेश में हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में करियर काउंसलिंग की सुविधा

भोपाल। प्रदेश में शासकीय हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिये करियर काउंसलिंग एवं गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। उचित चयन श्रेष्ठ करियर कार्यक्रम में कक्षा 9वीं एवं 11वीं में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाये हैं। उनके अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उसी कक्षा में प्रवेश के लिये काउंसलिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री का जताया आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को 4 सड़क परियोजनाओं की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश को सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश को सड़क अधोसंरचना निर्माण और क्षेत्रीय विकास में एक बड़ी सौगात दी गई है। उन्होंने कहा कि ये सड़कें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी और औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी ने बुधवार को मध्यप्रदेश के लिए 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 4302.93 करोड़ रुपये है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर मध्यप्रदेश को मंजूरी की गई इन परियोजनाओं की जानकारी साझा की है। केन्द्र सरकार के इस अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय पर डॉ. यादव ने आशा जताई है कि ये सड़कें परियोजनाएं प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सहज एवं सुगम बनाने के साथ आर्थिक विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

स्पेशल खबर राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से मध्यप्रदेश को मिलेगी रफ्तार...

4,302.87 करोड़ लागत की 4 सड़क परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

भोपाल(काप्र)।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि प्रदेश को 4,302.87 करोड़ रुपये लागत की 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की केन्द्र सरकार से स्वीकृति मिलने से मध्यप्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी के मार्गदर्शन में देश का अधोसंरचना क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास यात्रा की गति और तेज हो रही है।

संदलपुर से नसरुल्लागंज बायपास तक बनेगा 43.200 किमी का 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग:भोपाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-146बी के संदलपुर से नसरुल्लागंज बायपास तक के 43.200 किलोमीटर लंबे खंड को 1535.66 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह खंड एक महत्वपूर्ण धमनी मार्ग के रूप में

कार्य करता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-47, राष्ट्रीय राजमार्ग-46 और राष्ट्रीय राजमार्ग-45 को आपस में जोड़ता है। यह क्षेत्र अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला है, जिसे पेव्ड शोल्डर सहित 4 लेन किए जाने से यातायात की समग्र दक्षता में सुधार होगा। मालवाहन और आमजन के लिए यह मार्ग अब और भी सुचारु, सुरक्षित और समय बचाने वाला होगा।

राहतगढ़ से बेरखेड़ी तक बनेगा 10.079 किमी का 4 लेन कॉरिडोर:विदिशा और सागर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग-146 के राहतगढ़ से बेरखेड़ी तक के 10.079 किमी हिस्से को 731.36 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन में विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जो न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, बल्कि राहतगढ़ जैसे घनी आबादी वाले शहर को बायपास कर एक तेज और निर्बाध मार्ग प्रदान करेगी। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और राष्ट्रीय राजमार्ग-346 को जोड़ेगी। इसके साथ ही मार्ग के ज्यामितीय सुधार एवं रि-अलॉयमेंट से सामान और लोगों को आवाजाही और भी सुरक्षित व कुशल हो

सकेगी। इससे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

लहदरा से बेरखेड़ी गुरु तक बनेगा 20.193 किमी लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड बायपास:राष्ट्रीय राजमार्ग-146 पर लहदरा गांव जंक्शन से राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के बेरखेड़ी गुरु गांव जंक्शन तक 20.193 किमी लंबे 4-लेन ग्रीनफील्ड सागर पश्चिमी बायपास के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना पर कुल 688.31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग-146 शहरी बस्तियों और अत्यधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। नए बायपास के बनने से सागर शहर में यातायात का दबाव कम होगा, साथ ही यात्रा का समय और दूरी दोनों घटेंगे। यह परियोजना क्षेत्र के नागरिकों को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी।

पश्चिमी ग्वालियर के लिए 28.516 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस कंट्रोल्ड 4-लेन बायपास को स्वीकृति:ग्वालियर शहर के पश्चिमी हिस्से में 28.516 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस कंट्रोल्ड 4 लेन बायपास के निर्माण को केन्द्र सरकार ने

1347.6 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मुरैना और ग्वालियर जिलों के साथ-साथ रास्ते में आने वाले अन्य प्रमुख ब्लॉकों और तहसील मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा। यह नया सड़क खंड एक धमनी मार्ग की तरह कार्य करेगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-46, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और आगामी आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इसके विकास से भारी माल ढुलाई और लंबे मार्ग की यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा। परियोजना के पूर्ण होने के बाद यातायात का सुगम और सुरक्षित प्रवाह सुनिश्चित होगा तथा यात्रा के समय में काफी कमी आएगी। यह बायपास न केवल क्षेत्रीय विकास को गति देगा बल्कि आर्थिक और परिवहन संबंधी गतिविधियों को भी बल प्रदान करेगा।

इन परियोजनाओं से न केवल मध्यप्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, बल्कि यातायात सुरक्षा, मालवाहन दक्षता, समय की बचत, और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। आने वाले वर्षों में ये सड़कें प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।